

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-8

देहरादून: दिनांक: 21 जून, 2016

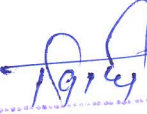
विषय:- अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकरणों के संबंध में एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने विषयक।

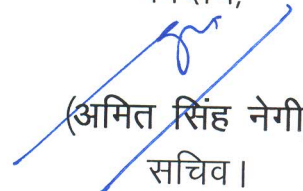
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-6171/आयु०क०उत्तरा०/प०सं०-56 (08-09)/विधि०-अनु०/2015-16/दे०दून, दिनांक 31.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकरणों के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01.04.2016 से उस समय तक, जब तक राज्य सरकार योजना को समाप्त न कर दे या जी०एस०टी० लागू होने तक जो भी पहले घटित हो, तक के लिये समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- समाधान योजना से संबंधित शासन के निर्देश, प्रार्थना पत्र एवं शपथ-पत्र के प्रारूप आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया इन योजनाओं का अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

  
अनुभाग  
आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून

भवदीय,  
  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

